भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1483
दिनांक 28.07.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत में निवेश

1483. श्री राजेन्द्र धेड्या गावितः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में निवेश के लिए मध्य पूर्व देशों के अग्रणी व्यवसायियों को आमंत्रित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त देशों के अग्रणी व्यवसायियों से किन मुख्य क्षेत्रों में निवेश की अपेक्षा कर रही है; और

(ग) अग्रणी व्यवसायियों की भारत में व्यापार करने में आसानी के संबंध में व्यापार के अवसरों के संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(डॉ. राजकुमार रंजन सिंह)

(क) से (ग) भारत के व्यापार और निवेश सहित कई क्षेत्रों में मध्य पूर्वी देशों के साथ व्यापक संबंध हैं। मध्य पूर्वी क्षेत्र के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ निवेश पर उच्च स्तरीय कार्य बल (एचएलटीएफआई), सऊदी अरब के साथ रणनीतिक साझेदारी परिषद (एसपीसी), भारत–इज़राइल सीईओ मंच आदि जैसे कई जी2 जी और बी2 जी तंत्र हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स और निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा इस क्षेत्र के साथ नियमित रूप से उच्च–स्तरीय व्यावसायिक सहभागिताएं आयोजित की जाती हैं। हाल ही में, "निवेश, व्यापार और सेवाओं में नए क्षितिज" विषय पर छठा भारत–अरब साझेदारी सम्मेलन, 11–12 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें अरब राज्यों और भारत के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यवसायी शामिल हुए थे।

सरकार ने निवेशक अनुकूल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति भी लागू की है जिसमें अधिकांश क्षेत्र ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% इक्विटी भागीदारी के लिए खुले हैं। भारत मध्य पूर्वी देशों के निवेशकों सहित वैश्विक निवेशकों के लिए अपने क्षेत्रों को खोलना जारी रखा है और नियामक बाधाओं संबंधी उनकी चिंताओं का समाधान करता है। मध्य पूर्वी देशों के कई सरकारी स्वामित्व वाली पूंजी निधि और कंपनियों जैसे सऊदी अरब का पब्लिक इनवेस्टमेंट फंड (पीआईएफ), यूएई का एडीआईए, डीपी वर्ल्ड, लुलु ग्रुप, कतर इनवेस्टमेंट ऑथिरिटी आदि ने खाद्य, ऊर्जा, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और अवसंरचना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया है।

*****